



सरकारी अधिकारियों के खिलाफ जाँच हेतु पूर्व अनुमोदन

प्रलिस के लिये:

पूर्व अनुमोदन, [सर्वोच्च न्यायालय \(SC\)](#), [प्रथम सूचना रिपोर्ट \(FIR\)](#), कौशल विकास घोटाला मामले, [अपराध जाँच विभाग \(CID\)](#)।

मेन्स के लिये:

पूर्व अनुमोदन।

[स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस](#)

चर्चा में क्यों?

हाल ही में [सर्वोच्च न्यायालय \(SC\)](#) ने कथित कौशल विकास घोटाला मामले में [प्रथम सूचना रिपोर्ट \(First Investigation Report- FIR\)](#) को रद्द करने की आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री की याचिका को रद्द करने का फैसला सुनाया है।

- न्यायाधीशों के बीच असहमति इस बात को लेकर है कि क्या आंध्र प्रदेश अपराध जाँच विभाग (Crime Investigation Department- CID) को भ्रष्टाचार के आरोपी सार्वजनिक अधिकारियों के खिलाफ जाँच करने से पहले राज्य सरकार से 'पूर्व अनुमोदन' लेने की आवश्यकता थी।

क्या था सर्वोच्च न्यायालय का फैसला?

- सर्वोच्च न्यायालय ने [भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988](#) की धारा 17A की व्याख्या और प्रयोज्यता को रद्द करने का फैसला सुनाया है।
- एक न्यायाधीश ने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री के खिलाफ PC अधिनियम के तहत कथित अपराधों की जाँच करने के लिये पूर्व अनुमोदन आवश्यक थी। हालाँकि उन्होंने [रिमांड आदेश को रद्द करने से इनकार कर](#) दिया और राज्य को ऐसी अनुमति लेने की स्वतंत्रता दी।
- अन्य न्यायाधीश के अनुसार [धारा 17A का पूर्वव्यापी/भूतलक्षी रूप से कार्यान्वयन नहीं](#) किया जाएगा तथा FIR को रद्द करने से इनकार करने वाले उच्च न्यायालय के नरिणय को ज्यों का त्यों रखा जाएगा।
 - न्यायमूर्ति ने यह भी कहा कि रिमांड का विवादित आदेश तथा उच्च न्यायालय के नरिणय में [कोई अवैधता नहीं](#) है।
- एक समान मत न होने के कारणवश मामले को उचित नरिदेशों हेतु [भारत के मुख्य न्यायाधीश \(Chief Justice of India- CJI\)](#) को प्रेषित किया गया है।

आंध्र प्रदेश में कौशल विकास घोटाला क्या था?

- आंध्र प्रदेश में कौशल विकास घोटाले में पूर्व मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू के वरिद्ध कौशल विकास कार्यक्रम के लिये नरिधारतिधन राशिका [दुरुपयोग](#) करने का आरोप लगाया गया।
- वर्ष 2021 में 3,356 करोड़ रुपए का कौशल विकास प्रोजेक्ट की जाँच शुरू हुई।
- दिसंबर 2021 में चंद्रबाबू नायडू के वरिद्ध FIR दर्ज की गई। अपराध अन्वेषण विभाग (Crime Investigation Department- CID) ने आरोप लगाया कि परिधिोजना के लिये आवंटित लगभग [241 करोड़ रुपए का अंतरण पाँच शेल कंपनियों को किया गया था](#)।

सरकारी अधिकारियों के वरिद्ध जाँच हेतु पूर्व अनुमोदन क्या है?

- परिधि:
 - पूर्व अनुमोदन [जाँचकर्त्ताओं, विशेष रूप से अपराध अन्वेषण विभाग \(CID\) अथवा केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो \(Central Bureau of Investigation- CBI\)](#) जैसे अभिकरणों के लिये सरकारी अधिकारी के वरिद्ध भ्रष्टाचार के आरोपों की जाँच अथवा जाँच शुरू करने से पूर्व सरकार अथवा सक्षम प्राधिकारी से अनुमोदन प्राप्त करने की आवश्यकता को संदर्भित करता है।
 - किसी भी औपचारिक कार्रवाई, जैसे कि [FIR \(प्रथम सूचना रिपोर्ट\)](#) दर्ज करना या वसित्त जाँच करने से पहले यह मंजूरी आवश्यक है।

■ कानूनी प्रावधान:

- 'पूर्व अनुमोदन' की आवश्यकता **दिल्ली वशिष्ठ पुलिस स्थापना अधिनियम 1946** में संशोधन के माध्यम से शुरू किये गए कानूनी प्रावधानों में नहिं है, जसि बाद में **भ्रष्टाचार नविवरण अधिनियम, 1988** में शामिल किये गये ।
- यह शर्त पहली बार वर्ष 2003 में अपनाई गई थी, जसिमें कहा गया था कियदि आरोपी संयुक्त सचिव से ऊपर का पद रखता है तो **भ्रष्टाचार नविवरण अधिनियम के तहत अपराधों की जाँच करने से पहले** केंद्र सरकार की मंजूरी की आवश्यकता होगी ।
- हालाँकि SC ने वर्ष 2014 में इस आवश्यकता को रद्द कर दिया । इसके बाद, वर्ष 2018 में, भ्रष्टाचार नविवरण अधिनियम में संशोधन के माध्यम से एक समान प्रावधान (धारा 17A) को फेरि से पेश किये गये ।
 - इस प्रावधान के अनुसार, यदकिसी लोक सेवक पर अपने आधिकारिक कर्तव्यों का नरिवहन करते समय अधिनियम के तहत अपराध करने का आरोप लगाया जाता है, तो **पूछताछ या जाँच शुरू करने से पहले केंद्र या राज्य सरकार या सक्षम प्राधिकारी से** अनुमोदन की आवश्यकता होती है ।

■ तरक:

- 'पूर्व अनुमोदन' की आवश्यकता के पीछे तरक **सार्वजनिक अधिकारियों से जुड़े** भ्रष्टाचार के मामलों की पूछताछ की आवश्यकता को **संभावति आधारहीन या राजनीति से प्रेरति जाँच** से अधिकारियों की सुरक्षा के साथ संतुलति करना है ।
- इसे यह सुनिश्चित करने के लिये एक प्रकरियात्मक सुरक्षा के रूप में देखा जाता है कअनिवेषण/जाँच वविकपूर्ण ढंग से और उचित नरीक्षण के साथ की जाए, जसिसे अन्वेषण शक्तियों का दुरुपयोग रोका जा सके ।

पूर्व अनुमोदन के प्रावधान में क्या चुनौतियाँ हैं?

- 'पूर्व अनुमोदन' की आवश्यकता से यह **नरिधारति करना अत्यंत कठनि** हो जाता है कक्या कसि सार्वजनिक अधिकारी द्वारा अपने कर्तव्यों का नरिवहन करते समय कोई अपराध किये गये थे ।
- प्रारंभिक जाँच क्षमता के बनिा, **साक्ष्य एकतरति करना** और यह स्थापति करना **चुनौतीपूर्ण** हो जाता है कअधिकारी के खिलाफ कोई वैध मामला है या नही ।
- पुलिस अधिकारियों और जाँच एजेंसियों पर 'पूर्व अनुमोदन' प्राप्त करने का ज़मिमेदारी डालने से **भ्रष्टाचार के आरोपों** का तुरंत तथा प्रभावी ढंग से समाधान करने की उनकी क्षमता में बाधा आ सकती है ।
- यह ज़मिमेदारी जाँच प्रक्रिया को धीमा कर सकता है, जसिसे **संभावति रूप से भ्रष्ट अधिकारियों को जाँच से बचने** या अपनी गतिविधियों को जारी रखने में सहायता मलि सकती है ।

आगे की राह

- 'पूर्व अनुमोदन' से संबंधति मौजूदा कानून की व्यापक समीक्षा करने और हतिधारकों की चिंताओं को दूर करने के लिये संशोधनों पर वचिार करने की आवश्यकता है ।
- 'पूर्व अनुमोदन' द्वारा प्रदान की गई निगरानी और शीघ्र जाँच की आवश्यकता के बीच संतुलन की तलाश करने की आवश्यकता है । यह सुनिश्चित करने के लिये अनुमोदन प्राप्त करने के मानदंडों को परिष्कृत करने पर वचिार किये जाना चाहिये कइससे पूछताछ शुरू करने में अनावश्यक देरी न हो ।
- लोक अधिकारियों की जाँच के लिये 'पूर्व अनुमोदन' देने हेतु स्पष्ट और पारदर्शी मानदंड स्थापति करने की आवश्यकता है । इसमें आरोपों की गंभीरता या इसमें शामिल अधिकारी के पद के लिये सीमा नरिदष्टि करना शामिल हो सकता है ।